



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215479
CG-DL-E-16012020-215479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]
No. 12]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 14, 2020/पौष 24, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 14, 2020/PAUSHA 24, 1941

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2020

(मामला सं. ओआई-29/2019)

विषय : चीन जन. गण., सउदी अरब के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिमेथइल फार्माइड (डीएमएफ) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा.सं. 6/37/2019-डी जी टी आर.—1. समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिसे यहां "नियमावली" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे यहां "अधिनियम" भी कहा गया है) के अनुसरण में, बालाजी अमाइन लिमिटेड (जिसे यहां "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. सउदी अरब (जिसे यहां "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डिमेथइल फार्माइड (डीएमएफ) (जिसे यहां "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा डीएमएफ भी कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे यहां "प्राधिकारी" भी कहा

गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों को लागू किए जाने हेतु अनुरोध किया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हो रही है और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डीमिथाइल फारमामाइड है और इसे डीएमएफ के रूप में भी कहा गया है।

4. “डीमिथाइल फारमामाइड” एक रंगरहित, उच्च उबाल वाले पोलर एपप्रोटिक साल्वेंट है जिसमें एक विशेष गंध होती है। यह ताप पर स्थाई है और अपने डिस्टिलेशन तापक्रम श्रेणी के अंतर्गत है और यह स्वतंत्र रूप से पानी, एल्कोहल, ईथर, कीटोन, ईस्टर, कार्बन, डीसल्फाइड और क्लोरीन वाला तथा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है।

5. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग और प्रयोग को मोटे तौर पर नीचे दी गई श्रेणीओं में रखा जा सकता है:-

- क. फार्मासिटिकल निर्माण में सॉल्वेंट के रूप में
- ख. एक्रेलिक पोलीमर निर्माण में सॉल्वेंट के रूप में
- ग. डीएमएफ के डेरीवेटिव के सिन्थिसिस के लिए फीडस्टॉक के रूप में
- घ. कीट नाशक निर्माण में सॉल्वेंट के रूप में

6. विचाराधीन उत्पाद को प्राथमिक रूप से आयातों के समय सीमा शुल्क उप-शीर्षक 29211110 के अंतर्गत घोषित किया गया है। हालांकि, यह उप-शीर्षक सांकेतिक मात्र है और यह किसी भी प्रकार से विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद के आयातों की सूचना अन्य उप शीर्षकों के अंतर्गत दिए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया है। यह केवल उप सीमा शुल्क उप शीर्षक तक विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र तक सीमित करने के लिए उपयुक्त नहीं होगा और जो उत्पाद विवरण के लिए संगत है।

समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु जिसे भारत में पाटित किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित किए गए आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु और आवेदक द्वारा निर्मित विचाराधीन उत्पाद के तकनीकी विनिर्देशों, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम-उपयोगों में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों तकनीकी रूप से और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापित करने योग्य हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमावली के तहत “समान वस्तु” माना जाना चाहिए। इसलिए, वर्तमान जांच के उद्देश्य से, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को ‘समान वस्तु’ के रूप में माना जा रहा है, जो संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे संबद्ध वस्तुओं के लिए है।

घरेलू उद्योग

8. आवेदन मै० बालाजी अमाइन्स लिमि. द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने न तो संबद्ध वस्तु को देश से आयात किया है और न ही संबंधित देश में किसी संबद्ध देश के निर्यातक या निर्माता या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) में निहित प्रावधानों के संबद्ध में “घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से” किया गया है।

कथित पाटन का आधार

9. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन जन.गण को एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और नियमावली के अनुबंध-I के पैरा-7 और 8 के अनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के तहत विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद, प्रथमदृष्ट्या से यह निष्कर्ष निकाला है कि संरचित सामान्य मूल्य को छोड़ कर विकल्प इस मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए संभव नहीं हैं क्योंकि पूरे आयात चीनजन.गण सहित संबद्ध देशों से हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य को सामान्य और प्रशासनिक

व्ययों और उचित लाभों के लिए परिवर्धनों के बाद भली भाँति समायोजित करते समय भारत उमें उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारण किया है। आवेदक ने भारत से सऊदी अरब के लिए पीयूसी के निर्यात आदेश का प्रमाण प्रदान किया है जो पीओआई के बाहर की अवधि से संबंधित है। अन्य साक्ष्यों के अभाव में, प्राधिकरण ने कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल वैल्यू के माध्यम से सऊदी अरब के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

10. प्राधिकारी ने डी-जी-सी-आई-एंड-एस के लेनदेन-वार आंकड़ों के अनुसार, संबद्ध देशों से निर्यात कीमत की गणना की है। समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय भाड़े, दस्तावेजीकरण प्रभारों, और रख-रखाव एवं स्वीकृति प्रभारों के लिए समायोजन किया गया है।

11. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना-गत स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के संबंध में उल्लेखनीय पाटन मार्जिन को दर्शाता है जिसके माध्यम से यह दृष्टिगत होता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तुएं पाटित की जा रही हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

12. घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने कुल रूप में पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में एवं घरेलू उद्योग पर कीमत कटौती, कीमत ह्रास प्रभाव के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि इसके उत्पादन ने घरेलू उद्योग के लिए विक्रय कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत के परिणामस्वरूप घाटे में वृद्धि, नियोजित पूंजी पर आय में कमी और नकदी प्रवाह पर विपरीत प्रभाव डाला है। एक पाटनरोधी जांच की शुरुआत के औचित्य को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

13. घरेलू उद्योग के द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत् प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन और इस प्रकार के कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में तथा इस नियमावली के नियम-5 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 9 के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर अपने आप को संतुष्ट करने के बाद, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन के होने, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, यदि उसे लगाया जाए, तब वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए समुचित होगा कि सिफारिश करने के लिए जांच शुरू करते हैं।

संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन.गण और सऊदी अरब है।

जांच की अवधि

15. वर्तमान जांच में जांच की अवधि (इसके पश्चात 'पीओआई' के रूप में भी संदर्भित) 01 जनवरी, 2019 से 30 सितम्बर, 2019 (09 महीने) हैं। क्षति की जांच की अवधि में अप्रैल, 2016-मार्च, 2017, अप्रैल, 2017-मार्च, 2018, अप्रैल 2018-मार्च, 2019 और जांच की अवधि शामिल होगी।

प्रक्रिया

16. इस नियमावली के नियम-6 के दिए गए अनुसार सिद्धांतों का पालन वर्तमान जांच के लिए किया जायेगा।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों और संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से सभी संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु पृथक् रूप से सूचित किया जा रहा है।

18. अन्य कोई भी हितवद्ध पक्षकार नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और ढंग से जांच से संबंधित अपने अनुरोध भी कर सकते हैं। यह सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किया जा सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी**व्यापार उपचार महानिदेशालय****वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय****वाणिज्य विभाग****भारत सरकार****चौथातल, जीवनतारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,****नई दिल्ली-110001**

19. प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार से यह अपेक्षित है कि वह अनुरोध के अगोपनीय पाठ को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

समय-सीमा

20. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए ताकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऊपर दिए गए पते पर प्राधिकारी तक पहुंच सके। हालाँकि, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उक्त नियम की व्याख्या के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए सूचना देने वाले नोटिस को उस तिथि से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त किया गया होगा जिस दिन यह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजा गया था या प्रेषित किया गया था। निर्यातक देश का उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि कोई सूचना निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त जानकारी अपूर्ण है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

21. सभी इच्छुक पक्षों को तात्कालिक मामले में अपनी रुचि (व्याज की प्रकृति सहित) अंतरंग करने की सलाह दी जाती है और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं को दर्ज करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली का उत्तर सहित कोई अनुरोध करने वाले पक्षकारों (जिसमें उससे संबंधित परिशिष्ट/अनुबंध शामिल हो) से यह अपेक्षित है कि वे उस स्थिति में दो अलग-अलग क्षेत्रों में उसे प्रस्तुत करें जब उसके किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" का दावा किया गया हो।

(i) एक सैट पर गोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित) तथा

(ii) दूसरे सैट पर अगोपनीय अंकित होना चाहिए (शीर्ष, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका आदि सहित)।

23. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" अनुरोधों को स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" के रूप में अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकार अंकित किए गए बिना प्राप्त किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितवद्ध पक्षकारों को इस प्रकार के अनुरोधों का निरीक्षण

करने के लिए अनुमति देने हेतु स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रत्येक के 4 (चार) सैट में हार्ड कॉपी सहित प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

24. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना निहित होगी जो गोपनीय प्रकृति की है और/अथवा अन्य सूचना जो इस प्रकार की सूचना देने वाले के द्वारा गोपनीय के रूप में दावा की गई हो। सूचना के लिए जिसके संबंध में दावा गोपनीय के रूप में किया जाता है, अथवा वह सूचना जिसके संबंध में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया हो, सूचना देने वाले से यह अपेक्षित है कि वे दी गई सूचना के साथ-साथ इसके संबंध में भी सही कारण का विवरण उपलब्ध कराएं कि क्यों इस प्रकार की सूचना को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

25. अगोपनीय पाठ के लिए यह अपेक्षित है कि वह गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति हो और अधिमानतः इसे अनुक्रमित किया गया हो अथवा कवर किया गया हो (यदि अनुक्रमण संभव नहीं हो) और उसका सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है लेकिन यह उस सूचना पर निर्भर करेगा जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है। अगोपनीय सारांश विस्तृत ब्यौरे के साथ होने चाहिए जिसमें कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ को तर्कसंगत तरीके से समझा जा सके। हालांकि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार यह उल्लेख कर सकते हैं कि इस प्रकार की सूचना का सारांश नहीं किया जा सकता है और कारणों का एक विवरण प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि क्यों इसका सारांश किया जाना संभव नहीं है।

26. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के लिए अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा यदि सूचना देने वाले इस सूचना को सार्वजनिक करने के लिए या तो इच्छुक नहीं हैं अथवा सामान्य रूप में या सारांश रूप में इसके प्रकटन के लिए अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, तब प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

27. उसके सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना किया गया कोई अनुरोध अथवा गोपनीयता के संबंध में सही कारण का उल्लेख किए बिना किये गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

28. संतुष्ट होने पर और दी गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने पर प्राधिकारी इस प्रकार की सूचना को ऐसी सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विशिष्ट अधिकरण के बिना किसी पक्षकार को प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. इस नियमावली के नियम 6(7) के संबंध में, कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय पाठ वाले सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

30. यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच की अनुमति देने से इंकार करता है अथवा अन्य प्रकार से उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या इस जांच में पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचाता है तब प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम को रिकॉर्ड कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिशें, जिसे वे उचित मानते हों, कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 2020

(Case No.OI-29/2019)**Initiation of Anti-Dumping Original Investigation concerning imports of Dimethyl Formamide (DMF) from China PR & Saudi Arabia .**

F. No. 6/37/2019-DGTR.—1. M/s Balaji Amines Ltd. (hereinafter also referred to as “applicant”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules”) for Original Investigation of Anti-dumping Duty concerning imports of “**Dimethyl Formamide**” (hereinafter also referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC” or “DMF”), originating in or exported from China PR and Saudi Arabia (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. The Applicant has alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from the subject countries and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

Product under consideration

3. The product under consideration in the present investigation is Di Methyl Formamide and has also been referred as DMF.

4. ‘Di Methyl Formamide’, is a colourless, high boiling polar aprotic solvent with a characteristic odor. It is stable on heating and under its distillation temperature range and is freely miscible with water, alcohols, ethers, ketones, ester, carbon disulfide and chlorinated and aromatic hydrocarbons.

5. The application and uses of the subject goods can be broadly categorized as follows;

- a. As a solvent in pharmaceuticals manufacturing;
- b. As a solvents in Acrylic Polymers manufacturing;
- c. As a feedstock for synthesis of derivatives of DMF;
- d. As a solvent in pesticides formulations

6. The PUC is primarily declared under Customs subheading 29211110 at the time of imports. However, the subheading is indicative only and is not binding on the scope of the PUC since the chances of imports of PUC getting reported under other subheadings cannot be ruled out as claimed by the petitioner. It would not be appropriate to restrict the scope of PUC to customs subheading alone and what is relevant is the product description.

Like Article

7. The Applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods and the product under consideration manufactured by the applicant. The two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the AD Rules. Therefore, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry

8. The Application has been filed by M/s Balaji Amines Ltd.. The Applicant has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. On the basis of information available, the Authority is satisfied that the Application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of the provisions contained in Rule 2 (b) and Rule 5 (3) of the Rules.

Basis of Alleged Dumping

9. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and has requested to determine normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The Authority, after evaluating the options under Para 7 of Annexure I of the Rules, has prima facie concluded that the options other than Constructed Normal Value are not feasible for determination of Normal Value in this case since almost entire imports are from subject countries including China PR. Accordingly, the Authority has determined Normal Value on the basis of cost of production in India, duly adjusted, and after additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The Applicant has provided evidence of an export order of the PUC from India to Saudi Arabia which pertains to period outside POI. In absence of other evidence, Authority has determined the normal value for Saudi Arabia through Constructed Normal Value.

10. The Authority has computed the export price from subject countries as per DGCI&S transaction wise data. Adjustments have been made for ocean freight, insurance, inland freight, documentation charges, and handling and clearance charges.

11. The normal value and export price have been compared at ex-factory level, which prima facie show significant dumping margin in respect of the subject goods from the subject countries, thereby, indicating that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal link

12. Information furnished by the Applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms, price undercutting, and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of increase in losses, decline on return on capital employed, and cash flow, as a result of increase in imports of subject goods at a price below selling price and non-injurious price for the domestic industry. There is sufficient prima facie evidence of the injury being caused to the domestic industry by dumped imports from subject countries to justify initiation of an antidumping investigation.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

13. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic

industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Subject Countries

14. The subject countries in the present investigation are China PR and Saudi Arabia.

Period of Investigation

15. The Period of Investigation (hereinafter also referred to as “POI”) in the present investigation is 1st January, 2019 to 30th September, 2019 (9 months). The injury investigation period will cover the periods April 2016-March 2017, April 2017-March 2018, April 2018-March 2019 and the POI.

Procedure

16. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of information

17. The known exporters in the subject countries and their government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below. The information/ submission may be submitted to:

The Designated Authority
Directorate General of Trade Remedies
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street
New Delhi-110001

19. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time-Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting Countries. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

21. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:

- i. one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- ii. the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies in four (4) sets of each.

24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarised depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarisation is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority